

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष, 2022-2023 में किसानों की आय में वृद्धि किये जाने की क्या-क्या कार्य योजना थी और उस योजना से प्रदेश के किसानों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है?	वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को लाभान्वित करने के लिए निम्न योजनायें संचालित की गयी हैं :- 1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर समस्त पात्र (अर्ह) किसानों को लाभान्वित करना 2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०एम०) 4. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पी०एम०- कुसुम) 5. खेत-तालाब योजना 6. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर किसानों से क्रय केन्द्रों के माध्यम से क्रय करना 7. उन्नतशील आधारीय प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) 8. बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना। 9. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी०के०वी०वाई०) और नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती योजना को प्रोत्साहित करना 10. जनपद हमीरपुर में जैविक खेती विकास योजना 11. प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना 12. नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी 13. संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) 14. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम) 15. मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना 16. नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) NMEO-OS एवं नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ट्री बोर्न ऑयल सीड्स) NMEO- TBO 17. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 18. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना 19. प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना 20. पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 21. विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना 22. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के 45 जनपदों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), 30 जनपदों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत औद्योगिक विकास के कार्यक्रम कराना। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 75 जनपद औद्योगिक विकास कार्यक्रमों से आच्छादित है। औद्योगिक क्षेत्र में फलों के क्षेत्र विस्तार के लिए 5450 हे० क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केला, आम, अमरुद, लीची आदि फलों का रोपड़ कराना। प्रदेश में किसानों को गुणवत्ता युक्त रोपड़ सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 08 सेन्टर आफ एक्सीलेंस स्थापित कराये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के कृषकों को रोगमुक्त सब्जी पौध/बेहन उपलब्ध कराने हेतु 21 हाईटेक नर्सरी की स्थापना कराना।

	23. गन्ना किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक तकनीकी से बुवाई कर उत्पादकता और रिकवरी को बढ़ाया जाना एवं गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करना। 24. दिनांक 24 मई, 2020 से 45 नासवान प्रकृति के कृषि उत्पादों को मण्डी शुल्क से मुक्त करते हुए इनके व्यापार को मण्डी परिसर के बाहर किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। मण्डी परिसर के अन्दर इन वस्तुओं का व्यापार करने पर 1 प्रतिशत प्रयोक्ता प्रभार लगाया गया तथा विकास शुल्क से मुक्त रखा गया है। दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को मण्डी शुल्क को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादनों का बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग के योजनाओं के अर्न्तगत कुल धनराशि ₹० 1569.12 करोड़ व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 8146919 किसानों के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक प्रदेश के 26187170 किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे कुल धनराशि ₹0 59105.27 करोड स्थानान्तरित करते हुए लाभान्वित किया गया।																					
(ख) उत्तर प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि किये जाने की वित्तीय वर्ष, 2023-24 में क्या योजना है?	प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्न योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जिसका विवरण निम्नवत है :- <table><tr><td>1</td><td>राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार योजना</td><td>₹० 1.68 करोड</td></tr><tr><td>2</td><td>निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)</td><td>₹० 15.00 करोड</td></tr><tr><td>3</td><td>राज्य सहायित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)</td><td>₹० 15.00 करोड</td></tr><tr><td>4</td><td>आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (एफ०पी०ओ०)</td><td>625 एफ०पी०ओ० का गठन</td></tr><tr><td>5</td><td>जनपद कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना</td><td>01</td></tr><tr><td>6</td><td>नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करायी गयी है</td><td>20 विज्ञान केन्द्र</td></tr><tr><td>7</td><td>डिजिटल क्राप सर्वे (एग्रीस्टैक)</td><td>शुभारम्भ करना</td></tr></table>	1	राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार योजना	₹० 1.68 करोड	2	निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	₹० 15.00 करोड	3	राज्य सहायित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	₹० 15.00 करोड	4	आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (एफ०पी०ओ०)	625 एफ०पी०ओ० का गठन	5	जनपद कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	01	6	नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करायी गयी है	20 विज्ञान केन्द्र	7	डिजिटल क्राप सर्वे (एग्रीस्टैक)	शुभारम्भ करना
1	राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार योजना	₹० 1.68 करोड																				
2	निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	₹० 15.00 करोड																				
3	राज्य सहायित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	₹० 15.00 करोड																				
4	आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (एफ०पी०ओ०)	625 एफ०पी०ओ० का गठन																				
5	जनपद कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	01																				
6	नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करायी गयी है	20 विज्ञान केन्द्र																				
7	डिजिटल क्राप सर्वे (एग्रीस्टैक)	शुभारम्भ करना																				
(ग) वित्तीय वर्ष, 2022-23 की कार्य योजना के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में क्या-क्या बढ़ोतरी की गयी है?	उक्त योजनाओं में वर्ष 2023-24 में कुल 2350.44 करोड की धनराशि प्राविधानित की गयी है।																					
(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।																					
(ङ.) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता है।																					

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।